vinetur

चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 24% टैरिफ की रोक 10 जनवरी 2027 तक बढ़ाई

सीमित राहत से सितंबर के व्यापारिक संघर्षविराम का एक हिस्सा कायम है, जबकि बीजिंग ने अतिरिक्त 10% टैरिफ बरकरार रखा है

सोमवार, 9 नवंबर 2026



चीन ने सोमवार, 9 नवंबर को कहा कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24% टैरिफ और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर विशेष बंदरगाह शुल्क की रोक 10 जनवरी 2027 तक बढ़ाएगा। इससे बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच सितंबर में हुए व्यापारिक संघर्षविराम का एक हिस्सा कायम रहेगा।

चीन के राज्य परिषद के टैरिफ आयोग ने एक बयान में कहा कि यह विस्तार मंगलवार, 10 नवंबर से लागू होगा और दो महीने तक चलेगा। आयोग के अनुसार, यह कदम वॉशिंगटन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के दौरान बनी सहमति को लागू करने के लिए उठाया गया है।

बीजिंग ने कहा कि संघर्षविराम का विस्तार दोनों देशों की कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत स्थिर और अनुमानित नीतिगत

माहौल बनाने में मददगार होना चाहिए। साथ ही, चीन ने कहा कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 10% टैरिफ बरकरार रखेगा। इससे संकेत मिलता है कि राहत सीमित है और व्यापारिक दंड पूरी तरह वापस नहीं लिए जा रहे।

इस घोषणा से दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक संबंधों में से एक में तनाव कम करने की आंशिक प्रक्रिया जारी रहेगी। यह ऐसे समय हुआ है जब दोनों सरकारें बाजार तक पहुंच, रणनीतिक उद्योगों और निर्यात नियंत्रणों से जुड़े व्यापक विवादों पर विचार कर रही हैं। प्रशांत महासागर के आर-पार नियमित माल ढुलाई पर निर्भर कारोबारों के लिए इस फैसले से कम-से-कम अगले दो महीनों तक निलंबित उपायों के फिर लागू होने का तत्काल जोखिम टल गया है।

इसका असर पेय पदार्थों के कारोबार पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, चीन में बिक्री करने वाले अमेरिकी वाइन निर्यातकों को रोक जारी रहने तक माल भेजने और कीमत तय करने के लिहाज से अधिक अनुमानित माहौल मिल सकता है। बंदरगाह से जुड़े शुल्कों का निलंबन नए परिवहन खर्च का जोखिम घटाने में भी मददगार हो सकता है। हालांकि, लाभ सीमित रहेगा क्योंकि अतिरिक्त 10% टैरिफ अब भी लागू है।

चीन ने इस विस्तार के साथ वॉशिंगटन को चेतावनी भी दी। चीनी सरकार ने कहा कि उसने अमेरिका के उन बार-बार दिए गए बयानों पर ध्यान दिया है जिनमें अदालतों द्वारा रद्द किए गए टैरिफ की जगह अन्य व्यापारिक उपाय लागू करने की संभावना जताई गई है। बीजिंग ने कहा कि वह अमेरिका के कदमों पर करीबी नजर रखेगा और जरूरत के मुताबिक अपने जवाबी टैरिफ में बदलाव करेगा।

अलग-अलग घोषणाओं में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह चीन की अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में शामिल 11 अमेरिकी कंपनियों और निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल 16 अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करने वाले उपायों का निलंबन भी 10 जनवरी 2027 तक जारी रखेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि Hanwha Ocean की अमेरिका से जुड़ी पांच सहायक कंपनियों पर लगाए गए उपाय भी उसी तारीख तक निलंबित रहेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि चीन कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाली कुछ तकनीकों तथा उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण से छूट की अवधि भी बढ़ाएगा। चीन ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंधों का इस्तेमाल अपनी व्यापक आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में और बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ विवादों में दबाव बनाने के लिए किया है।

चीन के परिवहन मंत्रालय ने अलग से कहा कि वह अमेरिकी जहाजों के बंदरगाह पर लंगर डालने पर लगाए गए विशेष शुल्क 10 जनवरी 2027 तक निलंबित रखेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि समुद्री लॉजिस्टिक्स और जहाज निर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा की जांच भी उस तारीख तक स्थगित रहेगी। इन कदमों से न केवल शिपिंग कंपनियों, बल्कि उन आयातकों और निर्यातकों पर भी दबाव घटेगा जिन्हें शुल्क फिर लागू होने पर अधिक लॉजिस्टिक्स खर्च उठाना पड़ता।

ये ताजा फैसले वॉशिंगटन में शी और ट्रंप के शिखर सम्मेलन के बाद आए हैं। सम्मेलन में कुछ उत्पादों पर करीब 60 अरब डॉलर के टैरिफ घटाने पर सहमति हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के हिस्से 30-30 अरब डॉलर थे। इस समझौते में चीनी खिलौनों और घरेलू उपकरणों से लेकर अमेरिकी मांस, अनाज, कोयला और चिकित्सा उपकरणों तक के उत्पाद शामिल थे।

दोनों सरकारों ने व्यापार और निवेश के मुद्दों पर काम करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय कार्य समूह बनाने पर भी सहमति जताई थी। इन माध्यमों का मकसद व्यापक संबंधों में तनाव बने रहने के बावजूद बातचीत जारी रखना था।

सोमवार की घोषणा से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष नियंत्रित संघर्षविराम को बनाए रखने में अब भी हित देखते हैं, भले ही कई दंड लागू रहें और नए जवाबी कदमों का विकल्प खुला हो। चीन की भाषा से स्पष्ट है कि वह मौजूदा व्यवस्था को शर्तों के अधीन मानता है और अमेरिका की ओर से टैरिफ पर आगे की कार्रवाई बीजिंग की प्रतिक्रिया को उकसा सकती है।

फिलहाल, इस विस्तार से विनिर्माण, कृषि, शिपिंग और उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबारों को अधिक स्पष्ट समय-सीमा

मिलती है। यह भी दिखाता है कि लगातार तनाव के बावजूद बीजिंग और वॉशिंगटन व्यापारिक लागत में तेज बढ़ोतरी रोकने के लिए अस्थायी निलंबन और सीमित दायरे वाली छूटों का इस्तेमाल करने को तैयार हैं।